

[2025] 11 एस.सी.आर. 423: 2025 आईएनएससी 1286

**पी. अंजनप्पा (मृत) विधिक उत्तराधिकारियों के माध्यम से
बनाम
ए.पी. नंजुंदप्पा एवं अन्य।**

(सिविल अपील संख्या 3934/2006)
06 नवंबर 2025

[विक्रम नाथ और, संदीप मेहता और एन.वी. अंजारिया, न्यायाधीशगण]

विचारणीय मुद्दा

यह प्रश्न उठा कि क्या पंजीकृत विमोचन विलेख वैध और बाध्यकारी हैं, और यदि ऐसा है, तो वादी संख्या 2 और प्रतिवादी संख्या 3 की सदस्यता और शेयर हकदारियों पर उनका कानूनी प्रभाव क्या है; क्या 'पलुपट्टी-विभाजन विलेख' नामक दस्तावेज़ पर, हैसियत के अलगाव को स्थापित करने के साथ-साथ बाद के कब्जे और उपभोग की प्रकृति को सिद्ध करने जैसे अनुषंगी उद्देश्यों के लिए भरोसा किया जा सकता है; और विभाज्य संपत्ति में क्या-क्या शामिल है और पक्षों के बीच शेयरों का निर्धारण किस प्रकार किया जाना है, जिसमें अनुसूची "बी" की संपत्ति और अनुसूची "सी" की मद संख्या 17 के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई, तथा प्रतिवादी संख्या 6 के सह-स्वामित्व को किस सीमा तक संरक्षित रखा जाना है, ये सभी विषय शामिल हैं।

शीर्ष टिप्पणियां

पारिवारिक समझौता – संयुक्त पारिवारिक संपत्ति – पंजीकृत विमोचन विलेख दस्तावेज़ जिसे 'पालुपट्टी' (बंटवारा विलेख) का नाम दिया गया – इस पर निर्भरता – बंटवारे और अलग कब्जे के लिए मुकदमा – मुकदमे की अनुसूची में शामिल संपत्तियां तीन भागों में विभाजित थीं: अनुसूची ए – अचल संपत्तियां जो एक व्यक्ति (अब मृतक) की थीं, और संयुक्त पारिवारिक संपत्तियों के रूप में बनी रहीं; अनुसूची बी – पंजीकृत बिक्री विलेख के तहत खरीदी गई अचल

संपत्तियां; अनुसूची सी –चल संपत्तियां, जिनमें अन्य चीज़ों के अलावा, अनुसूची बी की संपत्तियों से किराए के रूप में प्राप्त राशि भी शामिल थी –सभी पक्ष एक ही साझा पूर्वज से अपनी वंशावली जोड़ते हैं –अनुसूची बी की संपत्तियों के बंटवारे को लेकर विवाद –वादी संख्या 1 और 2 द्वारा मुकदमे की अनुसूचियों में अपने कथित हिस्सों के बंटवारे और अलग कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया गया, साथ ही परिणामी हिसाब-किताब और मध्यवर्ती लाभ की भी मांग की गई –वादी ने यह तर्क दिया कि उक्त संपत्तियां संयुक्त परिवार की आय के साथ मिल गई थीं और इसलिए वे भी बंटवारे के अधीन थीं; जबकि प्रतिवादी ने यह तर्क दिया कि मृतक के जीवित रहते ही एक पंजीकृत विमोचन विलेख निष्पादित कर दिया गया था, और मृतक की मृत्यु के बाद बंटवारे को एक 'पालुपट्टी' (बंटवारा विलेख) में दर्ज किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप वे संपत्तियां उनके अलग कब्जे और उपभोग में थीं –विचारण न्यायालय ने एक प्रारंभिक डिक्री के माध्यम से मुकदमे को वादी के पक्ष में तय कर दिया –इसके विरुद्ध अपील करने पर, उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया – यथार्थता:

अभिनिर्धारित: हिंदू कानून के तहत, संयुक्त स्थिति को समाप्त करने के लिए एक स्पष्ट घोषणा की जा सकती है, चाहे वह लिखित रूप में हो या किसी अन्य माध्यम से; और इस तरह के विभाजन को प्रमाणित करने वाला कोई भी लिखित दस्तावेज़, विभाजन के तथ्य, की गई व्यवस्था और उसके बाद के कब्जे की प्रकृति को साबित करने के लिए साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होता है। परिवार के बीच हुआ कोई लिखित समझौता, यदि केवल यह स्पष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है कि उसके बाद पक्षों ने संपत्तियों को किस प्रकार अपने अधिकार में रखा और उनका उपभोग किया, तो ऐसे सीमित और गौण उपयोग के लिए उसका पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं है। पंजीकृत दस्तावेजों, पक्षों के बयानों और समकालीन राजस्व अभिलेखों सहित मूल अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात्, दोनों ही पंजीकृत 'रिलीज़ डीड' विधिवत सिद्ध पाए गए हैं और इनका पूर्ण विधिक प्रभाव है। – एक पंजीकृत रिलीज़ डीड ने 1956 में वादी संख्या 2 को सहदायिकी से अलग कर दिया और संयुक्त

पारिवारिक संपत्ति पर उसके किसी भी दावे को रोक दिया; और दूसरी डीड ने 1967 में प्रतिवादी संख्या 3 को सहदायिकी से अलग कर दिया और संयुक्त पारिवारिक संपत्ति पर उसके किसी भी दावे को रोक दिया। – परिणामस्वरूप, 1969 में मूल स्वामी की मृत्यु के समय, विद्यमान सहदायिकी में केवल वादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 5 ही शामिल थे। – बिना रजिस्टर्ड बँटवारा नामा—जिसमें 'पलुपट्टी' भी शामिल है—का इस्तेमाल कुछ सीमित और सहायक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है; जैसे कि संयुक्त परिवार की स्थिति और मालिकाना हक के अलग होने को साबित करना, कब्जे की प्रकृति को स्पष्ट करना, उसके तहत किए गए इंतज़ामों को दर्ज करना, और पक्षों के बाद के आचरण को प्रमाणित करना। – 'पलुपट्टी' के रूप में तैयार किया गया दस्तावेज़, सहायक उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य और विश्वसनीय है; यह साबित करता है कि 11.02.1972 से, वादी सं. 1 और प्रतिवादी सं. 5 के बीच संयुक्त स्थिति का विभाजन हो गया था, और उसके बाद दोनों ने विभाजन विलेख के तहत आवंटित संपत्तियों को अलग-अलग अपने अधिकार में रखा और उनका उपभोग किया। इस दस्तावेज़ को ऐसा 'हस्तांतरण' नहीं माना जाएगा जो अपने आप में किसी अधिकार को बनाता या समाप्त करता हो। – विभाजन योग्य संपत्ति समूह में 'अनुसूची ए और 'अनुसूची सी की मदें 1 से 16 शामिल होंगी। – इस समूह में वादी सं. 1, प्रतिवादी सं. 5, पाँचों बेटियों में से प्रत्येक, और दिवंगत बेटी (जिसका हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 को, उसकी संपत्ति के प्रतिनिधि के तौर पर दिया जाएगा) के हिस्से निर्धारित किए गए हैं। – वादी सं. 2 और प्रतिवादी सं. 3 को इसमें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। – 'अनुसूची बी और 'अनुसूची सी की मद 17 को इस विभाजन योग्य संपत्ति समूह से बाहर रखा गया है। – प्रतिवादी संख्या 5 और प्रतिवादी संख्या 6 इन्हें बराबर-बराबर हिस्सों में धारित करेंगे – निर्णय और डिक्री तथा प्रारंभिक डिक्री को अपास्त किया जाता है – निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार एक नई प्रारंभिक डिक्री प्रतिस्थापित की जाती है। [पैरा 7.9, 8.2, 8.4, 8.5, 8.9, 10, 11]

उद्धृत निर्णयजन्य विधि

प्रेम सिंह बनाम बीरबल [2006] सप. 1 एससीआर 692: (2006) 5 एससीसी 353; एलुमलाई बनाम एम. कमला [2023] 1 एससीआर 261: (2023) 13 एससीसी 27; सीता राम भामा बनाम रामवतार भामा [2018] 10 एससीआर 503: (2018) 15 एससीसी 130 पैरा 13 पर; येल्लापु उमा माहेश्वरी बनाम बुद्ध जगदीश्वरराव (2015) 16 एससीसी 787; के.जी. शिवलिंगप्पा बनाम जी.एस. ईश्वरप्पा (2004) 12 एससीसी 189; थुलासिधारा बनाम नारायणप्पा [2019] 8 एससीआर 212: (2019) 6 एससीसी 409; कल्याणी बनाम नारायणन (1980) सप. एससीसी298; अमतेश्वर आनंद बनाम वीरेंद्र मोहन सिंह (2006) 1 एससीसी148 – को रेफर किया गया।

अधिनियमों की सूची

साक्ष्य अधिनियम, 1872; भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023; हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956.

प्रमुख शब्दों की सूची

विभाजन; पृथक कब्ज़ा और उपभोग; पंजीकृत विमोचन दस्तावेज़; हिस्सेदारी अधिकार; पलुपट्टी; विभाजन विलेख; संपार्श्विक उद्देश्य; संयुक्त स्थिति का पृथक्करण; पश्चात कब्ज़ा और उपभोग; विभाज्य संपत्ति; संयुक्त परिवार की संपत्तियाँ; पंजीकृत बिक्री विलेख; प्रारंभिक आदेश; सहदायिकता; संयुक्त परिवार की संपत्ति; अपंजीकृत विभाजन विलेख; सीमित संपार्श्विक उपयोग; हस्तांतरण; अधिकारों का सृजन या समाप्ति; सीमांकन द्वारा विभाजन।

मामले की उत्पत्ति

सिविल अपीलिय अधिकार क्षेत्र: सिविल अपील नंबर 3934 /2006

बेंगलुरु स्थित कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांक 30.08.2005 के निर्णय और आदेश से, आर एफ ए संख्या 750/1994

अधिवक्तागण

अपीलार्थी की ओर से वकील:

जी एल विश्वनाथ, सीनियर वकील, सुश्री हेतु अरोड़ा सेठी, सुश्री ललित मोहिनी भट, सुश्री नयना तारा बी जी, राहुल जैन।

प्रतिवादियों की ओर से वकील:

शेखर देवासा, सीनियर वकील, राधाकृष्ण एस हेगड़े, प्रकाश चंद्र शर्मा, राजीव सिंह, टी. मुथन्ना, मनीष तिवारी, मेसर्स देवासा एंड कंपनी।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

विक्रम नाथ, न्यायाधीश.

1. यह वर्तमान सिविल अपील, कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु द्वारा 30 अगस्त 2005 को रेगुलर फर्स्ट अपील संख्या 750/1994 में पारित अंतिम निर्णय और डिक्री से उत्पन्न हुई है (जिसे इसके बाद "विवादास्पद निर्णय" कहा जाएगा); जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया और प्रधान सिविल न्यायाधीश, बेंगलोर ग्रामीण जिला द्वारा मूल वाद संख्या 146/1987 में 19 अगस्त 1994 को दिए गए निर्णय और प्रारंभिक डिक्री की पुष्टि की, जिसमें वाद-सूची में वर्णित संपत्तियों के विभाजन और पृथक कब्जे के लिए दायर वाद को डिक्री किया गया था। इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता स्वर्गीय पी. अंजनप्पा के कानूनी वारिस हैं, जिन्हें विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में पक्षकार बनाया गया था; और संदर्भ की सुविधा के लिए, पक्षों का वर्णन इसके बाद विचारण न्यायालय के समक्ष उनकी स्थिति के अनुसार किया जाएगा, जिसमें अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में संदर्भित किया जाएगा।
2. वर्तमान मामले को जन्म देने वाले तथ्य इसके बाद दिए गए हैं।
 - 2.1. दोनों पक्ष अपना वंश एक पिल्लप्पा से जोड़ते हैं, जिन्हें उनका साझा पूर्वज बताया गया है। उनकी विधवा मुनियम्मा को विचारण न्यायालय के समक्ष

प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में पक्षकार बनाया गया था। वादियों ने यह दलील दी कि पिल्लप्पा के चार बेटे थे, जिनके नाम थे: वादी संख्या 1 ए. पी. नंजुंदप्पा, वादी संख्या 2 वेंकटस्वामीअप्पा, प्रतिवादी संख्या 3 श्रीरामअप्पा, और प्रतिवादी संख्या 5 पी. अंजनअप्पा; और पाँच बेटियाँ थीं, जिनके नाम थे: वादी संख्या 3 नारायणअम्मा, वादी संख्या 4 सोनअम्मा, वादी संख्या 5 अंजनअम्मा, और प्रतिवादी संख्या 4 लक्ष्मअम्मा; इनके अलावा एक बेटी ऐसी भी थी जिसकी मृत्यु पिल्लप्पा से पहले ही हो गई थी और जिसका प्रतिनिधित्व इस मुकदमे में प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में किया गया था। प्रतिवादी संख्या 6 मुनिस्वामीअप्पा, वादी संख्या 3 के पति हैं और संयुक्त परिवार के सदस्य नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या 7, मुकदमे से संबंधित कुछ संपत्तियों के संबंध में एक पट्टेदार है। अन्य प्रतिवादी, जैसा कि पक्षकारों की सूची में दर्शाया गया है, व्यापक परिवार के सदस्य हैं।

2.2. वाद-सूची में वर्णित संपत्तियाँ तीन भागों में विभाजित थीं। अनुसूची "ए" में उन अचल संपत्तियों का विवरण था, जो मूल रूप से पिल्लप्पा की बताई जाती थीं और उसके बाद, वाद के पक्षकारों से मिलकर बने सहदायिकी परिवार के हाथों में संयुक्त पारिवारिक संपत्तियों के रूप में बनी रहीं। अनुसूची "बी" में उन अचल संपत्तियों का विवरण था, जिन्हें 25 अप्रैल 1974 की एक पंजीकृत विक्रय-विलेख के अंतर्गत, प्रतिवादी संख्या 5 और प्रतिवादी संख्या 6 के संयुक्त नामों से खरीदा गया था। अनुसूची "सी" में चल संपत्तियों का विवरण था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, अनुसूची "बी" की संपत्तियों से किराए के रूप में प्राप्त राशियों को दर्शाने वाली एक मद भी शामिल थी।

2.3. वादी पक्ष का संक्षिप्त मामला यह था कि अनुसूची "ए" में सूचीबद्ध संपत्तियां संयुक्त परिवार की संपत्तियां थीं जिनका विभाजन होना था और अनुसूची "बी" में सूचीबद्ध संपत्तियां, हालांकि प्रतिवादी संख्या 5 और प्रतिवादी संख्या

6 के संयुक्त नाम पर थीं, संयुक्त परिवार की आय से अधिग्रहित की गई थीं और उसमें समाहित थीं, और इसलिए वे भी विभाजन के अधीन थीं। यह भी दावा किया गया कि प्रतिवादी संख्या 7 को अनुसूची "बी" में शामिल मदों के संबंध में वार्षिक पट्टेदार के रूप में नियुक्त किया गया था, और प्रतिवादी संख्या 5 ने पट्टे की राशि एकत्र की थी, जिसे अनुसूची "सी" के भाग के रूप में हिसाब में लिया जाना था। वाद में कुछ कृषि कार्यों का भी उल्लेख किया गया था, जिसमें कैसुआरिना वृक्षारोपण भी शामिल था, और आय का हिसाब मांगा गया था।

- 2.4. प्रतिवादी संख्या 5 ने मुकदमे का विरोध किया। उनके मुख्य बचाव, जैसा कि उन्होंने प्रस्तुत किया, इस प्रकार थे: कि वादी संख्या 2 ने पिल्लप्पा के जीवनकाल में एक पंजीकृत विमोचन विलेख निष्पादित किया था; कि प्रतिवादी संख्या 3 ने वर्ष 1967 में एक पंजीकृत विमोचन विलेख निष्पादित किया था जिसमें उन्होंने संयुक्त परिवार की संपत्तियों में अपने अधिकार त्याग दिए थे; और यह कि वर्ष 1969 में पिल्लप्पा की मृत्यु के बाद, 11 फरवरी 1972 को वादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 5 के बीच पंचायतदारों की उपस्थिति में एक विभाजन हुआ था, जिसे एक पालुपट्टी ('पालुपट्टी' का अर्थ विभाजन विलेख या पारिवारिक समझौता समझौता है) में दर्ज किया गया था, जिसके अनुसार वे अलग-अलग कब्जे और उपभोग में थे और राजस्व अभिलेखों में अलग-अलग प्रविष्टियाँ की गई थीं। प्रतिवादी संख्या 5 ने आगे यह भी कहा कि अनुसूची "बी" की संपत्तियाँ उनकी स्व-अर्जित संपत्तियाँ थीं, कि प्रतिवादी संख्या 6 मात्र नाममात्र का ऋणदाता था, और वादी की बहनों का विवाह प्रथागत खर्चों सहित हुआ था और वे अचल संपत्तियों में हिस्सेदारी की हकदार नहीं थीं।

- 2.5. 2.5. प्रतिवादी संख्या 6, यद्यपि संयुक्त परिवार का सदस्य नहीं है, अनुसूची "बी" का संयुक्त क्रेता था और उसे इसी आधार पर प्रतिवादी बनाया गया। प्रतिवादी संख्या 7, अनुसूची "बी" का पट्टेदार होने के नाते, किराए के हिसाब-किताब के दावे का जवाब देने के लिए प्रतिवादी बनाया गया। शेष प्रतिवादियों को विभाजन के मुकदमे में आवश्यक पक्षकार के रूप में जोड़ा गया।
- 2.6. 2 जुलाई 1987 को, वादी संख्या 1 और वादी संख्या 2 ने नगर सिविल न्यायाधीश, बैंगलोर ग्रामीण जिला की अदालत में मूल वाद संख्या 146/1987 दायर किया, जिसमें वाद अनुसूची में अपने कथित हिस्से के विभाजन और अलग कब्जे की मांग की गई थी, साथ ही मध्यवर्ती लाभ सहित परिणामी खातों की भी मांग की गई थी।
- 2.7. समन की तामील होने पर प्रतिवादी संख्या 5 उपस्थित हुआ और मुकदमे का विरोध किया। प्रतिवादी संख्या 6 ने यद्यपि पहले लिखित बयान दाखिल नहीं किया था, लेकिन बाद में प्रतिवादा दायर करते हुए अनुसूची "बी" की संपत्तियों में संयुक्त क्रेता के रूप में अपना आधा हिस्सा होने का दावा किया और अनुसूची "सी" में मद संख्या 17 के रूप में वर्णित राशि में भी उसी अनुपात में हिस्सा मांगा। प्रतिवादी संख्या 7 ने एक लिखित बयान दाखिल किया जिसमें उसने अनुसूची "बी" के संबंध में पट्टेदार होने की अपनी स्थिति स्वीकार की और कहा कि प्रतिवादी संख्या 5 को किराया तब तक दिया जाता रहा जब तक कि प्रतिवादी संख्या 5 और प्रतिवादी संख्या 6 के बीच विवाद उत्पन्न नहीं हो गए, जिसके बाद पट्टेदार ने अदालत में किराया जमा करने की इच्छा व्यक्त की। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने मामले का विरोध नहीं किया और अनुपस्थित रहे।

3. विचारण न्यायालय ने अभिवचनों और साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात्, 19 अगस्त 1994 के एक प्रारंभिक डिक्री द्वारा विभाजन और पृथक कब्जे के वाद को डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित कारणों पर आधारित था:

3.1. अनुसूची "ए" के संबंध में, विचारण न्यायालय ने यह माना कि ये संपत्तियाँ संयुक्त परिवार की संपत्तियाँ थीं। इसने 11 फरवरी 1972 को एक अपंजीकृत 'पालुपट्टी' के आधार पर किए गए बँटवारे के बचाव को अस्वीकार कर दिया। विचारण न्यायालय ने यह दर्ज किया कि चूँकि यह दस्तावेज़ अपंजीकृत था, इसलिए इसे पारिवारिक स्थिति में अलगाव या शेयरों की मात्रा को साबित करने के लिए साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता था; और यह भी कि आस-पास के राजस्व संबंधी दस्तावेज़ों से यह ज़ाहिर नहीं होता था कि कथित बँटवारे पर अमल किया गया था। विचारण न्यायालय ने यह भी पाया कि राजस्व अभिलेखों में दर्ज प्रविष्टियाँ बँटवारे के बजाय विरासत और प्रबंधन के आधार पर कब्जे को दर्शाती थीं; कि बँटवारे के अनुसार ज़मीन का कोई उप-विभाजन या सीमांकन नहीं किया गया था; और यह कि प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा जिस आचरण पर भरोसा किया गया था, जिसमें परिवार के कर्ज़ चुकाने के लिए बाद में की गई संपत्ति की बिक्री भी शामिल थी—वह पहले हो चुके पूर्ण अलगाव की स्थिति के साथ मेल नहीं खाता था।

3.2. अनुसूची "बी" के संबंध में, विचारण न्यायालय ने पाया कि संपत्तियाँ प्रतिवादी संख्या 5 और प्रतिवादी संख्या 6 के संयुक्त नामों से 25 अप्रैल 1974 की एक पंजीकृत विक्रय विलेख के तहत खरीदी गई थीं, और यह कि प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में दी गई लीज़ प्रतिवादी संख्या 5 और प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित की गई थी। मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के मूल्यांकन के आधार पर, जिसमें प्रतिवादी संख्या 5 से प्राप्त स्वीकारोक्तियाँ भी शामिल थीं, विचारण न्यायालय ने इस दलील को खारिज

कर दिया कि प्रतिवादी संख्या 6 केवल एक नाममात्र का व्यक्ति था, और इस तर्क को भी नकार दिया कि संपूर्ण अनुसूची "बी" प्रतिवादी संख्या 5 की स्व-अर्जित संपत्ति थी। विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी संख्या 6 अनुसूची "बी" में आधे हिस्से का, और अनुसूची "सी" की मद संख्या 17 द्वारा दर्शाई गई धनराशि में आधे हिस्से का हकदार था; जबकि इन मदों का शेष आधा हिस्सा बँटवारे के लिए पारिवारिक संपत्ति का हिस्सा माना गया।

3.3. प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा प्रस्तुत रिलीज़ डीड्स के संबंध में, विचारण न्यायालय ने यह माना कि वादी संख्या 2 से संबंधित पंजीकृत रिलीज़ डीड पर अमल होना सिद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि इसके प्रस्तुतकर्ता ने वादी संख्या 2 के संयुक्त परिवार से अलग होने या बँटवारे के उसके दावे को खारिज करने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। जहाँ तक प्रतिवादी संख्या 3 का प्रश्न है, विचारण न्यायालय ने रिलीज़ डीड पर संज्ञान लिया और उसे उत्तरजीविता के प्रयोजन हेतु अलग हुआ माना, तथापि यह निर्णय दिया कि पिता की मृत्यु पर होने वाली काल्पनिक वृद्धि में उसे भी उसके हिस्से के अनुपात में भागीदारी प्राप्त होगी। इसी आधार पर, विचारण न्यायालय ने वादी संख्या 2 अथवा प्रतिवादी संख्या 3 में से किसी को भी वाद से पूर्णतः बाहर करने से इनकार कर दिया।

3.4. शेरों की गणना इस आधार पर की गई थी कि, वर्ष 1969 में पिल्लप्पा की मृत्यु के समय, सह-दायभागी परिवार में पिता और तीन बेटे शामिल थे, जिनका नाम वादी सं. 1, वादी सं. 2, और प्रतिवादी सं. 5 था; जबकि प्रतिवादी सं. 3 को उत्तरजीविता के उद्देश्य से अलग माना गया था। इसलिए, पिल्लप्पा के पक्ष में 1/4 हिस्से का एक काल्पनिक विभाजन माना गया। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर कार्यवाही आगे बढ़ाई कि पिल्लप्पा का वह

काल्पनिक 1/4 हिस्सा, मुकदमे में शामिल नौ हिस्सेदारों के बीच बराबर-बराबर बँट गया; ये हिस्सेदार थे: वादी सं. 1, वादी सं. 2, प्रतिवादी सं. 5, चार बेटियाँ, पहले से मृत बेटी की शाखा जिसका प्रतिनिधित्व प्रतिवादी सं. 2 कर रहा था, और प्रतिवादी सं. 3। इस आधार पर, उन नौ लोगों में से प्रत्येक को 1/36 का अतिरिक्त हिस्सा मिला; और वादी सं. 1, वादी सं. 2, तथा प्रतिवादी सं. 5 में से प्रत्येक ने, इसके अतिरिक्त, अपने सह-दायभागी हिस्से के रूप में 1/4 हिस्सा और लिया। इस प्रकार, वादी सं. 1, वादी सं. 2, और प्रतिवादी सं. 5 में से प्रत्येक का कुल हिस्सा 5/18 हो गया; जबकि वादी सं. 3, वादी सं. 4, वादी सं. 5, प्रतिवादी सं. 4, प्रतिवादी सं. 3, और प्रतिवादी सं. 2 में से प्रत्येक का हिस्सा 1/36 रहा। प्रतिवादी सं. 6 का हिस्सा अलग से निर्धारित किया गया; यह हिस्सा 'अनुसूची "बी"' का 1/2 भाग और 'अनुसूची "सी"' की मद सं. 17 का 1/2 भाग था। यह निर्धारण पारिवारिक संपत्ति के कुल हिस्से से बाहर रखते हुए, उन मदों के संबंध में दर्ज निष्कर्षों के आधार पर किया गया था।

- 3.5. विचारण ट्रायल कोर्ट ने मध्यवर्ती लाभों और परिणामी खातों की जांच का निर्देश दिया, जिसमें अनुसूची "बी" से संबंधित पट्टे की रकम भी शामिल है, जिसे अंतिम डिक्री कार्यवाही में घोषित शेयरों के अनुसार निकाला जाना है।
4. 19 अगस्त 1994 के प्रारंभिक डिक्री से व्यथित होकर, प्रतिवादी संख्या 5 ने बेंगलुरु स्थित कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष नियमित प्रथम अपील संख्या 750/1994 दायर की। 30 अगस्त 2005 के विवादित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया और ट्रायल कोर्ट के डिक्री को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ पुष्ट कर दिया:
 - 4.1. हाई कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 5 के इस बचाव पर गौर किया कि 11 फरवरी 1972 को एक बँटवारा हुआ था, जिसे 'पालुपट्टी' के रूप में लिख लिया गया

था, और उसके बाद राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कब्ज़ा दिखाया गया था। दस्तावेज़ और उससे जुड़े अन्य सबूतों की जाँच करने के बाद, हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि पालुपट्टी, जो कि रजिस्टर्ड नहीं थी, उसे न तो संयुक्त परिवार की स्थिति में अलगाव साबित करने के लिए और न ही हिस्सों के बँटवारे को साबित करने के लिए सबूत के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है। इसके अलावा, म्यूटेशन के अंशों, अधिकारों के रिकॉर्ड और अन्य राजस्व कागज़ात की जाँच करने पर कोर्ट ने पाया कि उनमें दर्ज विवरण किसी बँटवारे के आधार पर नहीं, बल्कि विरासत और प्रबंधन के आधार पर कब्ज़ा होने का संकेत देते थे; कि बँटवारे के अनुरूप ज़मीन का कोई 'फोडी' या उप-विभाजन (फोडी का मतलब है ज़मीन की पैमाइश और सीमांकन की प्रक्रिया) नहीं हुआ था; और यह कि बाद में ज़मीन की बिक्री, जिसमें संयुक्त परिवार के कर्ज़ चुकाने की बात कही गई थी, वह पहले हुए किसी बँटवारे की बात से मेल नहीं खाती थी। इसलिए, 11 फरवरी 1972 को प्रभावी रूप से बँटवारा होने की दलील को खारिज कर दिया गया।

- 4.2. वादी संख्या 2 से संबंधित माने गए 'रिलीज़' के संबंध में, हाई कोर्ट ने विचारण न्यायालय से सहमति जताई कि यह दस्तावेज़ अमल में लाया गया था, ऐसा दिखाया नहीं जा सका; और इस बात का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं था कि वादी संख्या 2 अलग हो गया था, जिससे कि वह बँटवारे में या पिता के 'काल्पनिक हिस्से' के हस्तांतरण में अपने दावे से वंचित हो जाए। जहाँ तक प्रतिवादी संख्या 3 से संबंधित माने गए 'रिलीज़' का सवाल है, हाई कोर्ट ने उस दस्तावेज़ की प्रकृति और उस पर लागू होने वाली स्टैप संबंधी ज़रूरतों का हवाला दिया, और यह माना कि दस्तावेज़ पेश करने वाला पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि वह दस्तावेज़ प्रतिवादी संख्या 3 को पूरी तरह से बाहर करने के लिए प्रभावी है। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा

दर्ज किए गए कारणों में कुछ और बातें जोड़ीं, और शेयरों की गणना के उद्देश्य से प्रतिवादी संख्या 3 को शामिल किए जाने के निर्णय में कोई बदलाव करने से इनकार कर दिया।

- 4.3. अनुसूची "बी" के संबंध में, उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष की पुष्टि की कि संपत्तियाँ प्रतिवादी संख्या 5 और प्रतिवादी संख्या 6 के नाम पर संयुक्त रूप से खरीदी गई थीं, और प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में लीज़ उन दोनों द्वारा ही निष्पादित की गई थी। प्रतिवादी संख्या 5 के साक्ष्य में की गई स्वीकारोक्तियों और दस्तावेजों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि प्रतिवादी संख्या 6 केवल एक नाममात्र का व्यक्ति था, और अनुसूची "बी" में उसके आधे हिस्से के अधिकार को तथा अनुसूची "सी" की मद संख्या 17 के अंतर्गत आने वाली धनराशि में उसके आधे हिस्से के अधिकार को बरकरार रखा। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि विभाजन के लिए पारिवारिक संपत्ति के पूल में इन मदों का केवल शेष आधा हिस्सा ही शामिल किया जाएगा।
- 4.4. उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर, उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा अपनाई गई गणना की पुष्टि की, अर्थात् यह कि वादी संख्या 1, वादी संख्या 2, और प्रतिवादी संख्या 5 में से प्रत्येक पारिवारिक हिस्से में $5/18$ का हकदार होगा; और यह कि वादी संख्या 3, वादी संख्या 4, वादी संख्या 5, प्रतिवादी संख्या 4, प्रतिवादी संख्या 3, और प्रतिवादी संख्या 2 में से प्रत्येक $1/36$ का हकदार होगा; जबकि प्रतिवादी संख्या 6, पारिवारिक हिस्से से बाहर, अनुसूची "B" का $1/2$ और अनुसूची "सी" की मद संख्या 17 का $1/2$ अपने पास रखेगा।

- 4.5. अनुसूची "बी" के संबंध में पहले जमा किए गए किराए के वितरण के लिए, पुष्ट किए गए शेयरों के अनुपात में, परिणामी निर्देश जारी किए गए; और वाद-शीर्षक में कुछ लिपिकीय सुधारों की अनुमति दी गई।
5. प्रथम अपील खारिज होने से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने, जो विचारण अदालत के समक्ष प्रतिवादी संख्या 5 के कानूनी वारिस हैं, वर्तमान दीवानी अपील दायर की है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 निरीक्षण न्यायालय के समक्ष वादी संख्या 1 से 5 हैं। प्रतिवादी संख्या 6 निरीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 है, प्रतिवादी संख्या 7 प्रतिवादी संख्या 2 है, प्रतिवादी संख्या 8 प्रतिवादी संख्या 3 है, प्रतिवादी संख्या 9 प्रतिवादी संख्या 6 है, प्रतिवादी संख्या 10 प्रतिवादी संख्या 4 है, और प्रतिवादी संख्या 11 प्रतिवादी संख्या 7 है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, पक्षों को आगे उनके विवरण के अनुसार संदर्भित किया जाएगा, जैसा कि वे निरीक्षण न्यायालय के समक्ष थे।
6. अभिवचनों, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य तथा संबंधित पक्षों के परस्पर विरोधी प्रस्तुतीकरणों पर विचार करने के पश्चात्, हमारे द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले प्रश्न निम्नलिखित हैं:
- क्या दिनांक 09.11.1956 (प्रदर्श डी 15) और 14.09.1967 (प्रदर्श डी 16) के पंजीकृत रिलीज़ डीड वैध और बाध्यकारी हैं, और यदि हाँ, तो वादी संख्या 2 और प्रतिवादी संख्या 3 की सदस्यता और शेयर हकदारियों पर उनका कानूनी प्रभाव क्या है।
 - क्या दिनांक 11.02.1972 के दस्तावेज़, जिसे 'पालुपट्टी' (अनुसूची प्रदर्श डी - 17(ए) के साथ प्रदर्श डी 17) के रूप में नामित किया गया है, पर, हैसियत के विच्छेद को स्थापित करने के साथ-साथ बाद के कब्जे और उपभोग की प्रकृति को सिद्ध करने के लिए, संपार्श्विक प्रयोजनों हेतु भरोसा किया जा सकता है?

iii. उपरोक्त प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर, यह निर्धारित करना कि विभाजन योग्य संपत्ति में क्या-क्या शामिल है, और पक्षों के बीच शेयरों का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा—जिसमें 'अनुसूची "बी"' की संपत्ति और 'अनुसूची "सी"' की मद संख्या 17 के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही, तथा प्रतिवादी संख्या 6 के सह-स्वामित्व को किस सीमा तक सुरक्षित रखा जाना है, ये सभी बिंदु शामिल हैं।

7. विचारणीय मुद्दे - दोनों विमोचन विलेखों की वैधता और प्रभाव।

7.1. पक्ष इस बात पर असहमत हैं कि क्या वादी सं. 2 और प्रतिवादी सं. 3 ने, 1969 में मूल स्वामी की मृत्यु से पहले, प्रभावी रूप से खुद को संयुक्त परिवार से अलग कर लिया था और उसकी संपत्ति (तथा काल्पनिक बँटवारे पर पिता के हिस्से) पर अपने सभी दावों को छोड़ दिया था। वादियों का तर्क है कि कथित त्याग-पत्र या तो सिद्ध नहीं हुए, या, यदि सिद्ध भी हुए, तो "उन पर अमल न किए जाने" के कारण निष्प्रभावी थे। अपीलकर्ता (प्रतिवादी सं. 5) का कहना है कि दोनों दस्तावेज़ पंजीकृत त्याग-पत्र हैं जो प्रतिफल के बदले निष्पादित किए गए थे—जैसा कि पक्षों के बाद के आचरण से स्पष्ट होता है और ये वादी सं. 2 तथा प्रतिवादी सं. 3 को किसी भी हिस्से से वंचित करने का कार्य करते हैं।

7.2. पंजीकृत दस्तावेजों, पक्षों के बयानों और समकालीन राजस्व दस्तावेजों सहित मूल अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, हम संतुष्ट हैं कि प्रदर्श डी -15 और प्रदर्श डी 16 दोनों विधिवत सिद्ध हैं और कानूनी रूप से प्रभावी हैं।

7.3. जहां तक प्रदर्श डी-15 (09.11.1956) का संबंध है, यह एक पंजीकृत विलेख है जिसके द्वारा वादी संख्या 2 ने नकद भुगतान के बदले संयुक्त परिवार और अपने पिता की संपत्ति में अपने अधिकार और हित को स्पष्ट रूप से त्याग दिया। इसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि खून के बंधन को छोड़कर सभी

दावों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया गया है। यह विलेख बिना किसी आपत्ति के प्रस्तुत और प्रदर्शित किया गया; इसके निष्पादन या इसकी विषयवस्तु पर प्रतिवादी संख्या 5 से कोई जिरह नहीं की गई; और वादी संख्या 2 ने दस्तावेज़ को चुनौती देने के लिए जिरह के लिए स्वयं को उपस्थित नहीं किया। इन परिस्थितियों में, पंजीकृत दस्तावेज़ से जुड़ी वैधानिक धारणा लागू होती है, और प्रदर्श डी-15 के मामले में, जो प्रस्तुत किए जाने के समय तीस वर्ष से अधिक पुराना था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 90/भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 89 के तहत भी धारणा लागू होती है। दस्तावेज़ की प्रामाणिकता और प्रभाव को खंडन करने का भार उन लोगों पर था जिन्होंने इस पर सवाल उठाया था। कोई विश्वसनीय खंडन प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सिद्धांत को इस न्यायालय ने प्रेम सिंह बनाम बीरबल¹ में निम्नलिखित शब्दों में दोहराया है:

“27. यह माना जाता है कि पंजीकृत दस्तावेज़ वैध रूप से निष्पादित किया गया है। इसलिए, एक पंजीकृत दस्तावेज़ प्रथम दृष्टया कानून की दृष्टि से वैध होगा। इस प्रकार, साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व उस व्यक्ति पर होगा जो इस धारणा का खंडन करता है। इस मामले में, प्रतिवादी 1 उक्त धारणा का खंडन करने में सक्षम नहीं रहा है।”

- 7.4. ट्रायल कोर्ट ने दो आधारों पर प्रदर्श डी-15 को प्रभावी करने से इनकार कर दिया: पहला, यह कि विलेख का उल्लेख बाद के पलुपट्टी में नहीं था; और दूसरा, यह कि यह प्रदर्शित नहीं किया गया था कि इस पर "कार्रवाई" की गई थी। हमारी राय में, दोनों ही कारण निराधार हैं। किसी सहदायिक द्वारा प्रतिफल के बदले दी गई मुक्ति उसके मौजूदा सहदायिक हित को तुरंत समाप्त कर देती है; इसकी प्रभावशीलता किसी और क्रियान्वयन पर निर्भर

नहीं करती। बाद के, अलग ज्ञापन में मौन रहने से एक संपन्न, पंजीकृत त्यागपत्र निरस्त नहीं हो जाता, विशेष रूप से तब जब विलेख उचित अभिरक्षा से प्रस्तुत किया जाता है और जिरह में उसे चुनौती नहीं दी जाती।

- 7.5. तदनुसार, हम प्रत्युत्तर डी-15 को वैध और बाध्यकारी मानते हैं और यह मानते हैं कि इससे वादी संख्या 2 को 1956 से सहदायिकता से बाहर कर दिया गया है। प्रत्युत्तर डी-15 में जहां तक पिता के पृथक या भविष्य के हक का उल्लेख है, हम अनुबंध, प्रतिफल और दीर्घकालिक आचरण को वादी संख्या 2 के विरुद्ध अब विपरीत दावा प्रस्तुत करने के लिए एक न्यायसंगत विबंधन के रूप में मानते हैं। इसी प्रकार के विबंधन विलेखों के विबंधन प्रभाव को इस न्यायालय ने एलुमलाई बनाम एम. कमला² में इस प्रकार देखा था:

“16. इस न्यायालय ने लताफत हुसैन बनाम हिदायत हुसैन [लताफत हुसैन बनाम हिदायत हुसैन, 1936 एससीसी ऑनलाइन ऑल 315 : एआईआर 1936 ऑल 573] मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को अनुमोदित किया। न्यायालय ने निम्नलिखित पाया: (गुलाम अब्बास मामला [गुलाम अब्बास बनाम हाजी कयूम अली, (1973) 1 एससीसी 1], एससीसी पृष्ठ 4-5, पैराग्राफ 5 और 7)

“5. ... आदरपूर्वक, हम मद्रास उच्च न्यायालय के इस मत से सहमत नहीं हैं कि [अब्दुल काफूर बनाम अब्दुल रजाक, 1958 एससीसी ऑनलाइन मद्रास 129] किसी अपेक्षा का त्याग, एक कथित लेकिन कानूनी रूप से अप्रभावी हस्तांतरण के रूप में, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 द्वारा अमान्य है। चूंकि यह हस्तांतरण के रूप में ही शून्य होगा, इसलिए धारा 23, अनुबंध अधिनियम पर निर्भर रहने की

कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि संपत्ति का कोई "हस्तांतरण" नहीं हुआ था, जो कि सही स्थिति थी, बल्कि एक साधारण अनुबंध था, जो केवल भविष्य में प्रभावी हो सकता था, तो इसका उद्देश्य निश्चित रूप से तत्काल हस्तांतरण करना नहीं था, जिसे मुस्लिम कानून का नियम अमान्य करता था। वास्तविक प्रश्न यह था कि क्या किसी हस्तांतरण या अनुबंध से अलग, कथित त्याग और मूल्यवान प्रतिफल की प्राप्ति के विलेखों में की गई घोषणाएँ कई वर्षों के आचरण का हिस्सा नहीं हो सकतीं, जिसे एक क्रम में लिया जाए तो एक संपूर्ण रूप से, यह संपत्ति के अधिकार के सफल दावे के विरुद्ध एक बाधा उत्पन्न करता है, जब वह अधिकार वास्तव में अस्तित्व में आता है। एक न्यायसंगत विबंधन तब कार्य करता है, जब इसके तत्व स्थापित हो जाते हैं, साक्ष्य के एक नियम के रूप में जो उन अधिकारों के दावे को रोकता है जो अन्यथा अस्तित्व में हो सकते हैं।

7. सर रोलैंड विल्सन ने अपनी पुस्तक "एंग्लो मोहम्मदन लॉ" में (पृष्ठ 260, पैराग्राफ 208) इस स्थिति को इस प्रकार बताया है:

उन पाठकों की सुविधा के लिए जो हिंदू विधि के सबसे प्रचलित संप्रदाय के अनुसार पिता और पुत्र के संयुक्त स्वामित्व से परिचित हैं, यह स्पष्ट रूप से बताना शायद उचित होगा कि मुस्लिम विधि में, रोमन और अंग्रेजी विधि की तरह, किसी भी जीवित व्यक्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। किसी भी उत्तराधिकारी का कोई प्रत्यावर्ती हित नहीं होता, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या संभावित। देखें अब्दुल वाहिद [अब्दुल वाहिद खान बनाम नूरान बीबी, 1885 एससीसी ऑनलाइन पीसी 4 : (1884-85) 12 आईए 91 : आईएलआर (1885) 11 कलकत्ता 597] जिसका अनुसरण हसन अली [हसन अली बनाम नाज़ो, 1889 एससीसी

ऑनलाइन ऑल 29 : आईएलआर (1889) 11 ऑल 456] में किया गया था। इसका विपरीत भी सत्य है: किसी भावी उत्तराधिकारी द्वारा अपने पूर्वज के जीवनकाल में किया गया त्याग विरासत प्राप्त होने के बाद वैध नहीं होता, और न ही उसके विरुद्ध लागू किया जा सकता है।

यह कथन, जहां तक इस पर लागू होता है, कानून के लिहाज से सही है, क्योंकि उत्तराधिकार की अपेक्षा का मात्र त्याग भावी उत्तराधिकारी के आचरण को बाध्य नहीं कर सकता। लेकिन, यदि भावी उत्तराधिकारी इससे आगे बढ़कर प्रतिफल प्राप्त करता है और इस प्रकार आचरण करता है कि वह मालिक को अपनी संपत्ति का निर्वाह न करने के लिए गुमराह करता है, तो उत्तराधिकारी को उस समय अपना अधिकार स्थापित करने से रोका जा सकता है जब वह निर्विवाद रूप से उसे प्राप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, इस कथन से एस्टोपेल का सिद्धांत अप्रभावित रहता है।

(जोर दिया गया)

17. अनुसूची 'ए' में सूचीबद्ध संपत्ति श्री चंद्रन की पैतृक संपत्ति नहीं थी। श्री चंद्रन को इस पर अधिकार तभी प्राप्त होता जब उनके पिता की मृत्यु बिना वसीयत किए हुई होती। इस प्रकार, वे केवल स्पष्ट उत्तराधिकारी थे। स्पष्ट उत्तराधिकारी द्वारा हस्तांतरण मात्र उत्तराधिकार की गारंटी होने के कारण किसी भी अधिकार को हस्तांतरित करने में अप्रभावी होता है। दूसरे शब्दों में, इस मामले के तथ्यों के अनुसार, केवल विमोचन विलेख के निष्पादन से कोई हस्तांतरण नहीं हुआ। इसका सीधा कारण यह है कि हस्तांतरणकर्ता, अर्थात् अपीलकर्ताओं के पिता के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं था जिसे वे हस्तांतरित या त्याग सकें। हालांकि, यदि

उनका आचरण ऐसा था कि उन्हें रोका जा सकता था, तो विमोचन विलेख का निष्पादन उनके अधिकार को खतरे में डाल देगा और इसलिए अपीलकर्ताओं के दावे पर भी एक अमिट छाया डालेगा, जब तक कि हमें अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री सिद्धार्थ अय्यर की अन्य दलीलों में कोई योग्यता न मिले।

- 7.6. अब प्रदर्श डी-16 (14.09.1967) की बात करें, तो यह एक पंजीकृत विलेख है जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने सभी अधिकार, स्वामित्व और हित पिता और तत्कालीन सह-भागीदारों के पक्ष में त्याग दिए और साथ ही साथ संपत्ति की सात वस्तुएँ प्राप्त कीं। निष्पादन को अभिवेदनों में स्वीकार किया गया; प्रतिवादी संख्या 3 ने कटघरे में आकर विलेख को स्वीकार किया; और दस्तावेज़ को प्रदर्शित किया गया। निचली अदालतों ने प्रदर्श डी-16 को अनुचित संदेह की दृष्टि से देखा। निचली अदालत ने इसे मोटे तौर पर "इस पर अमल नहीं किया गया" और विवरण-आधारित तर्क के आधार पर खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने यह स्वीकार करते हुए कि विलेख स्टाम्प शुल्क के प्रयोजनों के लिए विभाजन विलेख का चरित्र धारण करता है, इस आधार पर इसे प्रभावी करने से इनकार कर दिया कि उचित मूल्यांकन और स्टाम्प शुल्क प्रदर्शित नहीं किए गए थे और किसी भी मामले में, इस पर अमल नहीं किया गया था। यह दृष्टिकोण कई कारणों से अस्थिर है।
- 7.7. प्रथम, विलेख पंजीकृत है और साक्ष्य में स्वीकार किया गया था; स्टॉप शुल्क पर कोई समयोचित, विशिष्ट आपत्ति अंकन के चरण में तार्किक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाई गई थी, और चूंकि दस्तावेज़ साक्ष्य में स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए अपीलिय चरण में इस आधार पर इसकी स्वीकार्यता पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता है। द्वितीय, यदि कोई प्रदर्श डी-16 को पारिवारिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी देखे, तो कानून ऐसे समझौतों को बनाए रखने के

पक्ष में दृढ़ता से झुकता है जो करीबी रिश्तेदारों के बीच हुए हों, जहां प्रतिफल का आदान-प्रदान हुआ हो और कब्ज़ा प्राप्त हुआ हो। यहां, प्रतिफल और निष्पादन की स्पष्ट स्वीकृति दोनों मौजूद हैं। तृतीय, "कार्रवाई की गई" आपत्ति तथ्यों और सिद्धांत रूप में निराधार है। अभिलेख 1967 के बाद के सुसंगत आचरण को दर्शाता है, जो प्रतिवादी संख्या 3 के अलगाव के अनुरूप है: उसने इसके बाद सहदायिक अधिकारों का दावा नहीं किया; 11.02.1972 की बाद की पारिवारिक व्यवस्था वादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 5 के बीच हुई; और राजस्व प्रक्रिया और लेन-देन, जिनकी चर्चा हम पलुपट्टी पर विचार करते समय करेंगे, प्रतिवादी संख्या 3 के सहदायिक के रूप में बने रहने के साथ स्पष्ट रूप से असंगत हैं। जहाँ निष्पादन स्वीकार किया जाता है, प्रतिफल दिखाया जाता है, और बाद का आचरण अलगाव की पुष्टि करता है, वहाँ न्यायालयों को अतिरिक्त औपचारिकताओं के प्रमाण की मांग करके पंजीकृत त्यागपत्र को रद्द नहीं करना चाहिए।

- 7.8. अतः हम निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मुख्य कारणों को अस्वीकार करते हैं। निचली अदालत ने बाद के दस्तावेज़ में "उल्लेख न होने" और "कार्रवाई न करने" के दावे को, उन दस्तावेज़ों के लिए घातक मानकर गलती की, जबकि उनसे संबंधित स्वीकृतियाँ और अनुमान मौजूद थे। उच्च न्यायालय ने इस गलती को और बढ़ा दिया, जब उसने साक्ष्य में स्वीकार किए जाने और उसके मूल भाव को स्वीकार करने के बाद भी, स्टाम्प वर्गीकरण का सहारा लेकर दस्तावेज़ों के प्रभाव को नकार दिया, और यह समझने में विफल रहा कि दस्तावेज़ों का अपना प्रभाव था और बाद के आचरण से उन्हें बल मिला था।
- 7.9. रिकॉर्ड में मौजूद संचयी मूल्यांकन के आधार पर, हम मानते हैं कि प्रदर्श डी-15 ने वादी संख्या 2 को 09.11.1956 से सहदायिकता से अलग कर दिया

और संयुक्त परिवार की संपत्ति पर उसके किसी भी दावे को वर्जित कर दिया। इसके अतिरिक्त, हम यह भी मानते हैं कि प्रदर्श डी-16 ने प्रतिवादी संख्या 3 को 14.09.1967 से सहदायिकता से अलग कर दिया और संयुक्त परिवार की संपत्ति पर उसके किसी भी दावे को वर्जित कर दिया। परिणामस्वरूप, 1969 में याचिकाकर्ता की मृत्यु के समय, विद्यमान सहदायिकता में केवल वादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 5 ही शामिल थे। यह कानूनी स्थिति विभाजन योग्य संपत्ति की गणना और शेरों के निर्धारण को नियंत्रित करेगी, जिसका हम तीसरे मुद्दे के अंतर्गत विचार करेंगे।

8. मुद्दा II - क्या "पलुपट्टी" संयुक्त परिवार के विघटन और पक्षों के बाद के अलग कब्जे और उपभोग (सहयोगी उपयोग) को साबित करती है।

8.1. वादी यह मानने से इनकार करते हैं कि संयुक्त परिवार का कोई विभाजन या विघटन हुआ था और उनका तर्क है कि पलुपट्टी के रूप में वर्णित दस्तावेज एक अपंजीकृत विभाजन विलेख है जिसे किसी भी उद्देश्य से नहीं देखा जा सकता है। प्रतिवादी संख्या 5 का दावा है कि प्रदर्श डी-17 में एक पारिवारिक व्यवस्था दर्ज है जिसमें वादी संख्या 2 और प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पहले किए गए त्यागपत्रों के बाद वादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 5 के बीच स्थिति के अलगाव की स्पष्ट घोषणा है, कि वास्तव में उस व्यवस्था पर अमल किया गया था, और यह कि भले ही यह अपंजीकृत हो, फिर भी संयुक्त स्थिति के विघटन को साबित करने और बाद के कब्जे और उपभोग की प्रकृति को स्पष्ट करने के सीमित सहायक उद्देश्यों के लिए इसे स्वीकार किया जा सकता है।

8.2. एक अपंजीकृत विभाजन विलेख, जिसमें वर्तमान मामले में पलुपट्टी भी शामिल है, संयुक्त परिवार की स्थिति और स्वामित्व के पृथक्करण को सिद्ध करने, कब्जे की प्रकृति को स्पष्ट करने, उसके तहत किए गए समझौते को

दर्ज करने और पक्षों के बाद के आचरण को प्रमाणित करने के सीमित सहायक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसा कि इस न्यायालय ने सीता राम भामा बनाम रामवतार भामा, येल्लापु उमा माहेश्वरी बनाम बुद्ध जगदीश्वरराव और के.जी. शिवलिंगप्पा बनाम जी.एस. ईश्वरप्पा जैसे विभिन्न निर्णयों में देखा है। इसी बात को इस न्यायालय ने थुलासिधारा बनाम नारायणप्पा⁶ में निम्नलिखित अनुच्छेदों में स्पष्ट रूप से समझाया है:

9.4. यह ध्यान देने योग्य है कि दिनांक 23-4-1971 का वह विलेख, जिसके अंतर्गत वाद संपत्ति कृष्णप्पा के पक्ष में हस्तांतरित हुई थी, पंचायत और पंचों के समक्ष लिखित रूप में तैयार किया गया था और उस पर ग्रामवासियों/पंचायत के सदस्यों तथा परिवार के सभी सदस्यों, जिनमें वादी भी शामिल है, ने हस्ताक्षर किए थे। यद्यपि वादी ने इस बात पर विवाद किया कि विभाजन दस्तावेज़ (प्रदर्शित डी-4) के रूप में लिखित रूप में नहीं किया गया था, अभिलेख में मौजूद संपूर्ण साक्ष्यों और वादी के बयान (प्रतिवाद) पर विचार करने पर, उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वर्ष 1971 में मौखिक विभाजन हुआ था। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसे वह हिस्सा मिला है जो दिनांक 23-4-1971 के दस्तावेज़ (प्रदर्शित डी-4) से मेल खाता है। दिनांक 23-4-1971 के दस्तावेज़/विभाजन विलेख/पालुपट्टा का निष्पादन विभिन्न गवाहों की जांच द्वारा स्थापित और सिद्ध किया गया है। उच्च न्यायालय ने उक्त दस्तावेज़ पर विचार करने से इनकार कर दिया है। और/या दिनांक 23-4-1971 (एक्सट. डी-4) के दस्तावेज़ पर केवल इस आधार पर विचार किया जा सकता है कि इसके पंजीकरण की आवश्यकता है और इसलिए, चूंकि यह अपंजीकृत है, इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। हालांकि, जैसा कि इस न्यायालय ने काले [काले बनाम

निदेशक समेकन, (1976) 3 एससीसी 119] में कहा है कि ऐसा पारिवारिक समझौता, भले ही पंजीकृत न हो, ऐसे पारिवारिक समझौते के पक्षों के विरुद्ध पूर्ण रूप से विरोधक के रूप में कार्य करेगा। उपरोक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने एस. शनमुगम पिल्लई बनाम के. शनमुगम पिल्लई [एस. शनमुगम पिल्लई बनाम के. शनमुगम पिल्लई, (1973) 2 एससीसी 312] में अपने पूर्व के निर्णय पर विचार किया, जिसमें निम्नलिखित कहा गया था: (एस. शनमुगम पिल्लई मामला [एस. शनमुगम पिल्लई बनाम के. शनमुगम पिल्लई, (1973) 2 एससीसी 312], एससीसी पृष्ठ 319 (& 321, पैरा 13 और 22)

“13. न्यायसंगत रूप से, एस्टॉपिल, इलेक्शन, पारिवारिक समझौता आदि जैसे सिद्धांत केवल साक्ष्य के तकनीकी नियम नहीं हैं। न्याय प्रशासन में इनका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कानून का अंतिम लक्ष्य न्याय सुनिश्चित करना है। हाल के समय में पक्षों के बीच न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय इन सिद्धांतों पर उदारतापूर्वक निर्भर रहे हैं। हम इनके दायरे को सीमित करने में संकोच करेंगे।”

22. जैसा कि इस न्यायालय ने टी.वी.आर. सुब्बू चेट्टी के पारिवारिक चैरिटी मामले [टी.वी.आर. सुब्बू चेट्टी के पारिवारिक चैरिटी बनाम एम. राघवा मुदलियार, एआईआर 1961 एससी 797] में कहा है, यदि कोई व्यक्ति संभावित उत्तराधिकारी के रूप में अपने अधिकार की पूरी जानकारी रखते हुए ऐसा लेन-देन करता है जो उसके दावे के साथ-साथ संबंधित समय पर विरोधियों के दावे का भी निपटारा करता है, तो उसे उस समझौते से पीछे हटने की अनुमति नहीं दी जा सकती जब वास्तव में उत्तराधिकार खुल जाता है।

9.5. जैसा कि इस न्यायालय ने सुब्रया एम.एन. [सुब्रया एम.एन. बनाम विट्टला एम.एन., (2016) 8 एससीसी 705 : (2016) 4 एससीसी (सिविल) 163] में कहा है, पंजीकरण के बिना भी पारिवारिक समझौते/पारिवारिक व्यवस्था के लिखित दस्तावेज को उसके तहत की गई व्यवस्था और पक्षों के आचरण को स्पष्ट करने वाले सहायक साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, वादी ने भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि मौखिक विभाजन 23-4-1971 को हुआ था और उसने यह भी स्वीकार किया कि 3 से 4 पंचायत सदस्य भी उपस्थित थे। हालांकि, उसके अनुसार, इसे लिखित रूप में दर्ज नहीं किया गया था। इसलिए, वादी के इस मामले को स्वीकार करते हुए भी कि 23-4-1971 को मौखिक विभाजन हुआ था, दस्तावेज, प्रक्षेप संख्या... दिनांक 23-4-1971 का प्रदर्श डी-4, जिस पर उन्होंने और परिवार के अन्य सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं, संपत्ति के बंटवारे की सूची मानी जा सकती है। मौखिक बंटवारे के अनुसार सभी को अपना-अपना हिस्सा मिला। इसलिए, इसे उस समझौते के तहत किए गए समझौते और पक्षों के आचरण को स्पष्ट करने वाले सहायक साक्ष्य के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अतः, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने दिनांक 23-4-1971 के प्रदर्श डी-4 पर ध्यान न देकर और/या उस पर विचार न करके गंभीर त्रुटि की है।

- 8.3. हमने मूल प्रदर्श डी-17 और इसकी अनुसूची प्रदर्श डी-17(क) का परीक्षण अभिलेख में दर्ज रूप में अवलोकन किया है। वादी संख्या 1 ने अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए, जिन्हें प्रदर्श डी-6 के रूप में साक्ष्य में अंकित किया गया था। प्रतिवादी संख्या 5 और माता के हस्ताक्षर भी अंकित किए गए थे।

लेखन पर पंचायतदारों का सत्यापन है और इसे ग्राम लेखाकार द्वारा लिखा गया था। साक्ष्य प्रस्तुत करते समय, परीक्षण न्यायालय ने प्रदर्श डी-17 और प्रदर्श डी-17(क) को सहायक साक्ष्य के रूप में अंकित करने की अनुमति दी थी। 1972 के बाद की आसपास की सामग्रियां इस स्थिति के अनुरूप हैं। ऐसे उत्परिवर्तन और राजस्व प्रविष्टियां हैं जो 1972 के बाद की व्यवस्था और पूर्व की रिलीज़ों का उल्लेख करती हैं। राजस्व अभिलेख, जिनमें आरटीसी और अनुक्रमणिका के अंश शामिल हैं, वादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 5 के नाम पर उन्हीं सर्वेक्षण संख्याओं के लिए अलग-अलग दर्ज हैं जो प्रदर्श डी-17(क) में उन्हें आवंटित की गई हैं। 1972 से अलग निवास और अलग खाना पकाने की व्यवस्था स्वीकार की गई है। वादी संख्या 1 ने स्वतंत्र रूप से अपने हिस्से में आई भूमि को गिरवी रखा। वादी संख्या 1 ने 1972 के बाद स्वतंत्र रूप से संपत्ति अर्जित की और उसका हस्तांतरण किया। 2014 में, वादी संख्या 1 ने नगर पालिका प्राधिकरण के पक्ष में त्यागपत्र निष्पादित किया और विकास अधिकारों के हस्तांतरण के माध्यम से स्वतंत्र रूप से लेनदेन का मुद्रीकरण किया। प्रदर्श डी-17(ए) के तहत आवंटित भूमि अलग-अलग गांवों में स्थित है और वादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 5 के बीच कोई भी सर्वेक्षण संख्या समान नहीं है। यह सीमांकन द्वारा विभाजन के अभाव पर आधारित आपत्ति को पुष्ट करता है।

- 8.4. ऐसे मामलों में लागू होने वाले सिद्धांत सर्वविदित हैं। हिंदू कानून के तहत, संयुक्त स्थिति का विच्छेद लिखित या अन्य किसी स्पष्ट घोषणा द्वारा किया जा सकता है, और ऐसे विच्छेद को प्रमाणित करने वाला लिखित दस्तावेज विच्छेद, व्यवस्था और बाद के कब्जे के स्वरूप को सिद्ध करने के लिए स्वीकार्य है। इसी बात को इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने

कल्याणी बनाम नारायणन मामले में निम्नलिखित अनुच्छेदों में प्रतिपादित किया था:

“18. एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रदर्श पी-1 विभाजन विलेख नहीं है, इस अर्थ में कि यह संपत्ति को विभिन्न सहदायिकों के बीच सीमा-निर्धारण द्वारा विभाजित करने का इरादा नहीं रखता है। हालांकि, हिंदू कानून में संयुक्त परिवार और संयुक्त परिवार की संपत्ति के संबंध में “विभाजन” शब्द को एक विशेष अर्थ में समझा जाता है। यदि संयुक्त स्थिति का विघटन किसी विलेख, लिखित दस्तावेज या ऐसे विघटन को लाने के इरादे की स्पष्ट घोषणा द्वारा किया जाता है, तो यह विभाजन कहलाता है (देखें राघवम्मा बनाम चेंचम्मा [एआईआर 1964 एससी 136 : (1964) 2 एससीआर 933 : (1964) 1 एससीए 593]। विभाजन के लिए केवल इतना ही आवश्यक है कि संयुक्त परिवार के किसी सदस्य द्वारा स्वयं को परिवार से अलग करने के इरादे का एक निश्चित और स्पष्ट संकेत दिया जाए। इस प्रकार की सूचना, संकेत या प्रतिनिधित्व किस रूप में होना चाहिए? यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। एक और आवश्यकता यह है कि अलग होने के इरादे का यह स्पष्ट संकेत ऐसी घोषणा से प्रभावित व्यक्तियों को ज्ञात होना चाहिए। निर्णयों की समीक्षा से पता चलता है कि अलग होने का यह इरादा विभिन्न तरीकों से प्रकट किया जा सकता है। यह सूचना देकर या मुकदमा दायर करके हो सकता है। निस्संदेह, संकेत या सूचना संयुक्त परिवार के उन सदस्यों को दी जानी चाहिए जो ऐसी घोषणा से प्रभावित होने की संभावना रखते हैं।

8.5. इसके अलावा, लिखित रूप में दर्ज पारिवारिक व्यवस्था, जब केवल इस बात को समझाने के लिए उपयोग की जाती है कि पक्षों ने बाद में संपत्तियों को

कैसे धारण किया और उनका उपयोग किया, तो उस सीमित सहायक उपयोग के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। इसी बात को इस न्यायालय ने अमृतेश्वर आनंद बनाम वीरेंद्र मोहन सिंह के मामले में इस प्रकार कहा था:

“28. हालाँकि, अपीलकर्ताओं ने इस आधार पर आवंटन की वैधता पर सवाल उठाया कि पहले दो समझौते पंजीकृत नहीं थे। यह तर्क निराधार है। पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17(1), जहाँ तक यह प्रासंगिक है, के खंड (ख) के तहत, “गैर-वसीयती दस्तावेजों का पंजीकरण अनिवार्य है, जो वर्तमान या भविष्य में, किसी भी अधिकार, हक या हित, चाहे निहित हो या आकस्मिक, जिसका मूल्य एक सौ रुपये या उससे अधिक हो, अचल संपत्ति में सृजित, घोषित, आवंटित, सीमित या समाप्त करने का आशय रखते हों या ऐसा करने का कार्य करते हों।” धारा 17 की उपधारा (2) धारा 17(1)(ख) और (ग) की अनिवार्य आवश्यकताओं के अपवाद बनाती है। पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17(2) में बनाए गए अपवादों में से एक खंड (i) है। यह अपवाद “किसी भी समझौता विलेख” से संबंधित है। दूसरे शब्दों में, सभी समझौता विलेख उस अधिनियम के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता से मुक्त हैं। [देखें गोविंद राम बनाम मदन गोपाल, 72 आईए 76 : एआईआर 1945 पीसी 74, 76]। इस मामले में समझौता विलेख एक ही परिवार के सदस्यों के बीच उनके पारस्परिक लाभ के लिए किया गया एक लेन-देन था। अपीलकर्ताओं का यह तर्क नहीं है कि समझौतों को किसी अन्य अधिनियम के तहत पंजीकृत करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा, यह सिद्धांत भी है कि न्यायालय किसी पारिवारिक व्यवस्था को तकनीकी या तुच्छ आधारों पर बाधित करने के बजाय उसे

बरकरार रखने के पक्ष में होते हैं, विशेषकर तब जब पक्षों को उस व्यवस्था के तहत पारस्परिक लाभ प्राप्त हुए हों। [देखें काले बनाम उप निदेशक समेकन, (1976) 3 एससीसी 119 : एआईआर 1976] एससी 807]। दोनों निचली अदालतों ने सर्वसम्मति से पाया था कि पक्षों को समझौतों के तहत महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुए थे। हमने स्वयं भी इस पहलू पर रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की पुनर्व्याख्या की है और हमें विपरीत दृष्टिकोण अपनाने के लिए कुछ भी नहीं मिला है। इसके अलावा, इस मामले में समझौते न्यायालय के निर्णय में समाहित हो गए थे, जो पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 की उपधारा (2)(vi) के अंतर्गत भी अपवादित है [“17. (2)(vi) किसी न्यायालय का कोई निर्णय या आदेश, सिवाय उस निर्णय या आदेश के जो किसी समझौते पर आधारित हो और जिसमें अचल संपत्ति शामिल हो, सिवाय उस अचल संपत्ति के जो

मुकदमे या कार्यवाही का विषय है;”]।”

- 8.6. हमारी राय में, विखंडन की वास्तविकता का आकलन आचरण के संचयी मूल्यांकन द्वारा किया जाता है, जिसमें अलग-अलग कब्ज़ा, अलग-अलग खेती, अलग-अलग निवास, आवंटित भूमि के साथ स्वतंत्र व्यवहार और राजस्व अभिलेख शामिल हैं जो लगातार ऐसे अलगाव को दर्शाते हैं। जहां आवंटित भूमि अलग-अलग सर्वेक्षण संख्या वाले विभिन्न गांवों में स्थित है, वहां विखंडन का अनुमान लगाने के लिए आगे विभाजन पर जोर देना जांच को गलत दिशा में ले जाता है, क्योंकि निर्णायक प्रश्न यह है कि क्या संयुक्त स्थिति समाप्त हो गई थी और बाद का उपभोग अलग-अलग था।
- 8.7. इन सिद्धांतों पर परीक्षित, प्रदर्श डी-17 संपार्श्विक उपयोग के लिए योग्य है। यह उस समय के एकमात्र जीवित सह-भागीदारों, अर्थात् वादी संख्या 1 और

प्रतिवादी संख्या 5 के बीच मुक्ति के बाद की व्यवस्था को दर्ज करता है। इस पर स्वीकृत हस्ताक्षर और ग्राम बुजुर्गों का सत्यापन है। इसे निचली अदालत द्वारा संपार्श्विक प्रयोजनों के लिए चिह्नित किया गया था। इसके बाद के लंबे और निरंतर आचरण से 11.02.1972 को हुए विघटन की वास्तविकता की पुष्टि होती है। पक्षकार अलग-अलग रहते थे और अलग-अलग खाना बनाते थे। वे विभिन्न गांवों में अलग-अलग सर्वेक्षण संख्या वाली जमीनों पर खेती करते थे। वादी संख्या 1 ने गिरवी और बाद के लेन-देन सहित अपनी जमीनों का स्वामी के रूप में प्रबंधन किया। 2014 में नगरपालिका द्वारा भूमि त्याग और विकास अधिकारों का हस्तांतरण अकेले वादी संख्या 1 द्वारा किया गया था। यह संचयी मैट्रिक्स इस बात की पुष्टि करता है कि परिवार 11.02.1972 से संयुक्त नहीं रहा और उसके बाद प्रत्येक शाखा ने प्रदर्श डी-17(क) में आवंटित संपत्ति को अलग-अलग रखा और उसका उपयोग किया।

- 8.8. निचली अदालत और उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण जांच में खरा नहीं उतरता। निचली अदालत ने प्रदर्श डी-17 पर इस आधार पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया कि यह अपंजीकृत था और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, और उसने उत्परिवर्तन प्रविष्टि को इस प्रकार पढ़ा मानो यह विरासत या सहमति पर आधारित हो, न कि पलुपट्टी पर। यह दृष्टिकोण गलत है। लिखित दस्तावेज स्पष्ट रूप से संपार्श्विक उद्देश्यों के लिए चिह्नित किया गया था और उस स्तर पर पंजीकरण कोई बाधा नहीं थी। सीमांकन द्वारा विभाजन पर जोर देने से इस निर्विवाद स्थिति की अनदेखी हुई कि आवंटित भूमि अलग-अलग गांवों में है और सर्वेक्षण संख्याएँ आपस में मेल नहीं खाती हैं, और इसने राजस्व अभिलेखों में दर्ज लंबे समय से चले आ रहे पृथक कब्जे को भी नजरअंदाज कर दिया। निचली अदालत ने गिरवी अभिलेख को भी गलत तरीके से पढ़ा, जिसमें प्रतिवादी संख्या 5 की भागीदारी मान ली गई,

जबकि दस्तावेज और बैंक नोटिस में केवल वादी संख्या 1 को ही स्वामी के रूप में दर्शाया गया है। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के अवलोकन की पुष्टि की बिना स्वतंत्र रूप से उठे बिंदुओं को तैयार किए और उन पर निर्णय लिए, और बिना सभी संबंधित सामग्रियों पर विचार किए। इसलिए इसने एक्स.डी-17 के संपार्श्विक उपयोग और स्थापित आचरण के कानूनी प्रभाव पर ट्रायल कोर्ट के गलत निर्देश को ठीक नहीं किया।

8.9. 8.9. अतः हम यह मानते हैं कि प्रदर्श डी-17, प्रदर्श डी-17(क) के साथ पढ़ा जाए, तो यह इस बात को सिद्ध करने के सहायक प्रयोजनों के लिए स्वीकार्य और विश्वसनीय है कि 11.02.1972 से वादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 5 के बीच संयुक्त स्थिति का विच्छेद हो गया था और उसके बाद प्रत्येक ने प्रदर्श डी-17(क) के तहत आवंटित संपत्तियों को अलग-अलग धारण किया और उनका उपयोग किया। हम स्पष्ट करते हैं कि प्रदर्श डी-17 को ऐसा हस्तांतरण नहीं माना जाता है जो स्वतः ही अधिकारों का सृजन या समाप्ति करता हो। हमारा निष्कर्ष स्थिति के विच्छेद और बाद के कब्जे और उपयोग के स्वरूप पर आधारित है, जैसा कि लिखित दस्तावेज और आचरण की लंबी अवधि से स्पष्ट होता है।

8.10. अतः, दो परिणाम निकलते हैं और हिस्सेदारी तय करते समय इन पर विचार किया जाएगा। 11.02.1972 के बाद अधिग्रहित संपत्तियाँ किसी मौजूदा सहदायिक संपत्ति में वृद्धि नहीं करती हैं और किसी सिद्ध संयुक्त खरीद के अधीन, अधिग्रहणकर्ता की पृथक संपत्ति का हिस्सा बन जाती हैं। बेटियाँ, जो उस समय सहदायिक नहीं थीं, 2004 से पहले हुए किसी विघटन के कारण सहदायिक हिस्सेदारी प्राप्त नहीं करती हैं। गणनाएँ तीसरे मुद्दे के अंतर्गत की जाएँगी और संयुक्त रूप से खरीदी गई वस्तुओं में प्रतिवादी संख्या 6 के आधे हिस्से की रक्षा की जाएगी।

9. मुद्दा III - विभाजन योग्य पूल, आंशिक शेयरों और दिशाओं का परिणामी निर्धारण।
- 9.1. प्रदर्श डी-15 और प्रदर्श डी-16 को वैध मुक्तिपत्र मानते हुए और प्रदर्श डी-17 को प्रदर्श डी-17(क) के साथ पृथक्करण और बाद में अलग-अलग उपयोग के सहायक उद्देश्यों के लिए स्वीकार करते हुए, विभाज्य संपत्ति की पहचान की जानी चाहिए और सटीक हिस्से निर्धारित किए जाने चाहिए। विभाजन के लिए पारिवारिक संपत्ति में अनुसूची ए और अनुसूची सी की मद संख्या 1 से 16 शामिल होंगी। अनुसूची बी और अनुसूची सी की मद संख्या 17 पारिवारिक संपत्ति से बाहर रहेंगी। प्रतिवादी संख्या 5 और प्रतिवादी संख्या 6 के बीच अनुसूची बी और अनुसूची सी की मद संख्या 17 बराबर भागों में विभाजित होंगी, और इस निर्णय में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रतिवादी संख्या 6 के आधे हिस्से को कम करे।
- 9.2. 9.2. विभाजन योग्य संपत्ति पर आंशिक गणना, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की असंशोधित धारा 6 के तहत 1969 में पिलाप्पा की मृत्यु के समय किए गए काल्पनिक विभाजन का अनुसरण करती है। उस तिथि को, अनुसूची 'ए' के लिए विद्यमान सहदायिक व्यवस्था में पिलाप्पा, वादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 5 शामिल थे, क्योंकि वादी संख्या 2 और प्रतिवादी संख्या 3 ने पहले ही प्रत्युत्तर डी-15 और प्रत्युत्तर डी-16 निष्पादित कर दिए थे और इस प्रकार सहदायिक व्यवस्था से बाहर थे। उस समय के काल्पनिक विभाजन के अनुसार पिलाप्पा को 1/3, वादी संख्या 1 को 1/3 और प्रतिवादी संख्या 5 को 1/3 हिस्सा आवंटित किया जाएगा। पिलाप्पा का 1/3 हिस्सा उस समय जीवित उनके सात बच्चों, अर्थात् वादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 5 और पांच बेटियों के बीच उत्तराधिकार द्वारा वितरित किया जाएगा, जिसमें वादी संख्या 2 और प्रतिवादी संख्या 5 भी शामिल हैं। 3. उनके बाध्यकारी त्यागपत्रों के आधार पर, जो स्पष्ट रूप से पिलाप्पा की पैतृक और स्व-अर्जित

संपत्तियों तक विस्तारित थे, उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए, सातों बच्चों में से प्रत्येक पिलाप्पा के $1/3$ में से $1/7$ लेगा, जिससे प्रत्येक को $1/21$ प्राप्त होगा, इस प्रकार वादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 5 अपने-अपने $1/3$ में अतिरिक्त $1/21$ जोड़ लेंगे।

- 9.3. उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर, विभाजन योग्य संपत्ति अनुसूची क और अनुसूची ग की मद संख्या 1 से 16 तक है। इस संपत्ति में से वादी संख्या 1 को $8/21$ भाग, प्रतिवादी संख्या 5 को $8/21$ भाग और पांचों पुत्री शाखाओं में से प्रत्येक को $1/21$ भाग मिलेगा, जबकि दिवंगत पुत्री का $1/21$ भाग प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में उसकी संपत्ति के रूप में निर्धारित किया जाएगा। प्रदर्श डी-15 और प्रदर्श डी-16 के कारण वादी संख्या 2 और प्रतिवादी संख्या 3 को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अनुसूची ख और अनुसूची ग की मद संख्या 17 इस विभाजन में शामिल नहीं हैं। ये प्रतिवादी संख्या 5 और प्रतिवादी संख्या 6 के बराबर भागों में हैं।
10. अतः अपील स्वीकार की जाती है।
11. आरएफए संख्या 750/1994 में दिनांक 30.08.2005 का निर्णय और डिक्री तथा ओ.एस. संख्या 146/1987 में दिनांक 19.08.1994 की प्रारंभिक डिक्री को रद्द किया जाता है। इसके स्थान पर निम्नलिखित शर्तों के साथ एक नई प्रारंभिक डिक्री जारी की जाती है:
- i. प्रदर्श डी-15 और प्रदर्श डी-16 को वैध और बाध्यकारी विमोचन घोषित किया जाता है। प्रदर्श डी-17 को प्रदर्श डी-17(ए) के साथ पढ़ा जाए तो यह 11.02.1972 से संयुक्त स्थिति के विच्छेद को स्थापित करने और बाद के पृथक कब्जे और उपभोग की प्रकृति को स्पष्ट करने के सहायक उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य माना जाता है।

- ii. विभाजन योग्य संपत्ति में अनुसूची क और अनुसूची ग की मदें 1 से 16 शामिल होंगी। इस संपत्ति में हिस्सेदारी इस प्रकार निर्धारित की गई है: वादी संख्या 1 को 8/21, प्रतिवादी संख्या 5 को 8/21, और प्रत्येक पांच पुत्री शाखाओं को 1/21, जिसमें से दिवंगत पुत्री की 1/21 हिस्सेदारी प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में होगी, जो उसकी संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। वादी संख्या 2 और प्रतिवादी संख्या 3 को कोई हिस्सेदारी नहीं मिलेगी।
 - iii. अनुसूची बी और अनुसूची सी की मद संख्या 17 को इस संग्रह से बाहर रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 5 और प्रतिवादी संख्या 6 इन्हें बराबर भागों में रखेंगे।
 - iv. अनुसूची बी या अनुसूची सी के मद 17 से संबंधित कोई भी जमा राशि, पट्टा रसीदें, या अन्य संचय जो वर्तमान में अदालत में हैं या पट्टेदार के माध्यम से पता लगाए जा सकते हैं, अंतिम डिक्री की कार्यवाही में उचित भत्ते के अधीन, प्रतिवादी संख्या 5 और प्रतिवादी संख्या 6 के बीच समान रूप से विभाजित किए जाएंगे। अनुसूची ए और अनुसूची सी के मद 1 से 16 से संबंधित मध्यवर्ती लाभ, यदि कोई हो, तो अंतिम डिक्री की कार्यवाही में कानून के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे।
12. विचरण अदालत इस फैसले के अनुरूप अंतिम डिक्री तैयार करेगी। वह अनुसूची क और अनुसूची ग की मद संख्या 1 से 16 तक के हिस्से निर्धारित करेगी और अनुसूची ख और अनुसूची ग की मद संख्या 17 में प्रतिवादी संख्या 5 और प्रतिवादी संख्या 6 के बराबर हिस्सों को अलग-अलग प्रभावी करेगी। अनुसूची ख या अनुसूची ग की मद संख्या 17 से संबंधित कोई भी अंतरिम हस्तांतरण इन घोषणाओं के अधीन होगा और यदि आवश्यक हो, तो बराबर हिस्सों को प्रभावित किए बिना अंतिम डिक्री की कार्यवाही में उस पर विचार किया जाएगा।
13. खर्च के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

14. सभी लंबित अंतरिम आवेदन निपटा दिए गए हैं।
मामले का परिणाम: अपील मंजूर।

शीर्ष टिप्पणियाँ निधि जैन द्वारा तैयार किए गए हैं

यह अनुवाद अधिवक्ता ज्ञान रंजन, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।